

[2023] 3 एस. सी. आर. 413

/

जोली जॉर्ज और ए. एन. आर. वी.

जॉर्ज एलियास और एसोसिएशन और ओआरएस। (2022 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 1333-1335) अप्रैल 12, 2023

/

[वी. रामसुब्रमणियन और पंकज मिडल, जे. जे.]

केरल सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सुविधा अधिनियम, 2019, 2, 5, 6 और 10-केरल पंचायत राज अधिनियम, 1994-केरल पंचायत भवन नियम, 2019-नियम 68-'जी. ई. ए.' ने सड़क कार्य करने के लिए गर्म मिश्रित संयंत्र खरीदे-उन्होंने यू/एस. द्वारा एक पावती प्रमाण पत्र प्राप्त किया। 5 2019 के अधिनियम के तहत और संयंत्र की स्थापना के लिए लाइसेंस देने के लिए पंचायत को एक आवेदन प्रस्तुत किया-उन्होंने केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से "स्थापना के लिए सहमति" प्राप्त की-पंचायत के समक्ष उनका आवेदन ग्राम पंचायत द्वारा खारिज कर दिया गया था-आयोजित: यह स्वीकार किया जाता है कि 'जी. ई. ए.' ने केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापना के लिए सहमति प्राप्त की है और एस. के अंतर्गत एक पावती प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया है। 5(3) 2019 के अधिनियम-स्वीकृति प्रमाण पत्र का प्रभाव इस तरह होगा जैसे कि यह एस में परिभाषित एक अनुमोदन है। 2(ग)-केरल एमएसएमई अधिनियम की धारा 10 न केवल अन्य कानूनों पर अधिनियम को प्रबल प्रभाव प्रदान करती है, बल्कि 1994 के अधिनियम का एक विशिष्ट संदर्भ भी देती है -केरल एम. एस. एम. ई. अधिनियम की धारा 10 (2) यह स्पष्ट करती है कि 1994 के अधिनियम के प्रावधानों को केरल एम. एस. एम. ई. अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप होने के लिए संशोधित के रूप में पढ़ा जाएगा-इस प्रकार, 'जी. ई. ए.' की प्रार्थना वैधानिक प्रिस्क्रिप्शन के आलोक में दी जानी चाहिए।

/

/

/

/

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया : **1.** एकल न्यायाधीश और खंड पीठ के आदेश को नंगे पढ़ने से पता चलता है कि सबसे महत्वपूर्ण पहलू दृष्टिहीन हो गया है। मान लीजिए, रिट याचिकाकर्ताओं ने केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से इसे स्थापित करने के लिए सहमति प्राप्त की है। यह भी

स्वीकार किया जाता है कि रिट याचिकाकर्ताओं ने केरल एमएसएमई अधिनियम की धारा **5 (3)** के अंतर्गत एक पावती प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। ऊपर निकाली गई धारा **6 (1)** से यह देखा गया है कि एक पावती प्रमाण पत्र का प्रभाव होगा जैसे कि यह धारा **2 (सी)** में परिभाषित एक अनुमोदन है। ए के खिलाफ क्या माना जाता है

/

/

413

414 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 3 एस. सी. आर.

रिट याचिकाकर्ताओं को आज **1994** के अधिनियम के अंतर्गत अनुमति की आवश्यकता है। लेकिन केरल एमएसएमई अधिनियम की धारा **10** न केवल अन्य कानूनों पर अधिनियम को ओवरराइडिंग प्रभाव प्रदान करती है, बल्कि **1994** के अधिनियम का एक विशिष्ट संदर्भ भी देती है। रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा अपनी दूसरी रिट याचिका में की गई प्रार्थना, स्पष्ट रूप से वैधानिक प्रिस्क्रिप्शन के आलोक में दी जानी चाहिए। [पैरा **8,9,10** और **11**] [417-जी-एच; **418-ए, ई, जी; 419-ई**]

/

2. केरल एम. एस. एम. ई. अधिनियम **1994** के अधिनियम और कुछ अन्य स्थानीय अधिनियमों को दरकिनार करता है। यही कारण है कि रिट याचिकाकर्ताओं ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से "सहमति" ली है। एक बार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति लेने के बाद, पर्यावरण की रक्षा के उद्देश्य से केरल एमएसएमई अधिनियम की धारा **10** को पढ़ने की आवश्यकता पैदा नहीं होती है। [पैरा **16**] [420-ई-एफ]

/

टी. एन. गोडावर्मन तिरुमुलपद बनाम। भारत संघ और

ओआरएस। (2011) 7 एससीसी 338:[2011] 7 एससीआर 954; नगरपालिका

ग्रेटर मुंबई निगम (एम. सी. जी. एम.) बनाम अभिलाष

/

लाल और ओआरएस। (2020) 13 एससीसी 234:[2019] 14 एससीआर 659;

ए. पी. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाम प्रो.एम. वी. नायडू

() और ओआरएस। (1999) 2 एससीसी 718:[1999] 1 एस. सी. आर. 235-संदर्भित।

संदर्भित निर्णय

/

[2019] 14 एससीआर 659

संदर्भित

पैरा **15**

[1999] 1 एससीआर 235

संदर्भित

पैरा **15**

[2011] 7 एससीआर 954

संदर्भित

पैरा **17**

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2023 की सिविल अपील संख्या 2764-2766।

/

2021 के डब्ल्यू. ए. सं. 607,756 और 741 में एनर्कुलम में केरल उच्च न्यायालय के दिनांक 09.12.2021 के निर्णय और आदेश से।

सह

/

2023 की सिविल अपील संख्या 2767।

मेसर्स के. एम. एन. पी. विधि , सुश्री उत्तरा बब्बर, वी. श्यामोहन, सुश्री अंशिका बाजपेयी, मार्टिन जी. जॉर्ज, सुश्री रिया कालरा, के. परमेश्वर, हरीश वासुदेवन, सुश्री आरती गुप्ता, सुश्री कांति, कुरियाकोस वर्गीज, सी. के. सासी, ए.

/

415

जोली जॉर्ज और ए. एन. आर. वी.जॉर्ज एलियास और एसोसिएशन और ओआरएस।

अब्दुल्ला नसीह वी. टी., सुश्री मीना के. पौलोस, मैसर्स लॉफिक, श्रीराम परक्कट, एम. एस. विष्णु शंकर, आदित्य संतोष, सुश्री अथिरा जी. नायर, श्रीनाथ एस, जोगी स्कारिया, प्रदीप कुमार गुप्ता,

सुश्री बीना विक्टर, विवेक गुरुप्रसाद बालेकेरे, कीर्तिप्रियन ई, सुश्री एम. प्रिया, अधिवक्ता।
उपस्थित पक्षकारों के लिए।

/

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

वी. रामसुब्रमण्यन, जे.

अनुमति दी गई।

2. जॉर्ज एलियास एंड एसोसिएट्स, जो तीन अपीलों के पहले समूह में प्रतिवादी संख्या 1 हैं और जो चौथी अपील में अपीलकर्ता हैं, ने केरल उच्च न्यायालय की फाइल पर 2020 के डब्ल्यू. पी. (सी) Nos.10381 और 17920 में दो रिट याचिकाएं दायर कीं, जिसमें क्रमशः अनुरोध किया गया था कि (i) कल्लूरकाड़ ग्राम पंचायत की समिति के एक आदेश अपास्त करते हुए ते हुए उन्हें एक हॉट मिक्स प्लांट स्थापित करने के लिए लाइसेंस देने से इनकार कर दिया गया; और (ii) इस घोषणा के लिए कि केरल सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सुविधा अधिनियम, 2019 के अंतर्गत दिए गए प्रमाण पत्र के आधार पर, पंचायत के लाइसेंस सहित सभी लाइसेंस और अनुमोदन प्राप्त किए गए माने जाने चाहिए।

/

/

3. केरल उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश ने दिनांक 1 के एक सामान्य आदेश द्वारा दोनों रिट याचिकाओं का निपटारा कर दिया, जिसमें रिट याचिकाकर्ताओं को दो सप्ताह के भीतर केरल पंचायत भवन नियम, 2019 2 के नियम 68 के अंतर्गत अनुमति के लिए आवेदन करने की अनुमति दी गई थी और आगे पंचायत के सचिव को पंचायत द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों, यदि कोई हों, के अधीन आवश्यक अनुमति देने का निर्देश दिया गया था। विद्वान न्यायाधीश ने कहा कि चूंकि रिट याचिकाकर्ताओं ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति प्राप्त की थी, इसलिए पंचायत का सचिव नियम, 2019 के नियम 68 के अंतर्गत अनुमति देने से इनकार नहीं कर सकता है, हालांकि वह सामान्य शर्तें लगा सकता है।

/

/

4. विद्वान न्यायाधीश के उक्त आदेश को चुनौती देते हुए, तीन अंतर-न्यायालय अपील दायर की गईं। अदालत के भीतर की अपीलों में से एक रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा स्वयं दायर की गई थी, क्योंकि वे परिणाम से संतुष्ट नहीं थे। अन्य रिट अपीलें इलाके के कुछ लोगों द्वारा दायर की गई थीं, जिन्होंने हॉट मिक्स प्लांट की स्थापना पर आपत्ति जताई थी।

/

/

416

/

[2023] 3 एस सी आर।

/

5. केरल उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने दिनांक 09.12.2021 के एक सामान्य आदेश द्वारा अपीलों को खारिज कर दिया। इसलिए, इलाके के लोग तीन अंतर-अदालत अपीलों में केरल उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित सामान्य आदेश को चुनौती देने वाली पहली तीन अपीलों के साथ आए हैं। रिट याचिकाकर्ताओं ने एक अपील भी की है, जो चौथी है, क्योंकि वे उच्च न्यायालय से पूरी राहत नहीं मिलने से व्यथित हैं।

/

6. हमने सभी पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुना है। 7. इन अपीलों में हल किए जाने वाले विवाद को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है यदि हम इस मुकदमेबाजी की ओर ले जाने वाले संक्षिप्त तथ्यों पर एक नज़र डालें। ये संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:

/

(i) जॉर्ज एलियास एंड एसोसिएट्स, जिन्हें हम रिट याचिकाकर्ता के रूप में वर्णित करेंगे, केरल राज्य के विभिन्न हिस्सों में सड़क कार्यों में लगे हुए हैं। उन्होंने सड़क के कार्यों को पूरा करने के लिए हॉट मिक्स प्लांट खरीदे, जिसके लिए उन्हें अनुबंध मिले।

/

(ii) दिनांक 06.03.2019 के एक समझौते द्वारा, रिट याचिकाकर्ताओं को चेरथला अरूरकुट्टी में सड़क कार्य का अनुबंध दिया गया था। कुछ महीनों के भीतर, केरल एमएसएमई अधिनियम लागू हो गया और इसलिए रिट याचिकाकर्ताओं ने उक्त अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत एक पावती प्रमाण पत्र प्राप्त किया।

/

(iii) रिट याचिकाकर्ताओं ने हॉट मिक्स प्लांट की स्थापना के लिए लाइसेंस देने के लिए कल्लूरकाड पंचायत को एक आवेदन भी प्रस्तुत किया। आवेदन 05.02.2020 पर किया गया था।

/

(iv) 04.03.2020 केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर

"स्थापना के लिए सहमति" प्रदान की गई।

(v) चूंकि लाइसेंस के लिए आवेदन पर पंचायत से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी, इसलिए रिट याचिकाकर्ताओं ने केरल पंचायत राज (कारखानों, व्यापार, उद्यमिता गतिविधियों और अन्य सेवाओं को लाइसेंस जारी करना) नियम, 1996 के नियम 12 (3) के अंतर्गत डीमिंग प्रावधान के लाभ का दावा किया। तदनुसार, रिट याचिकाकर्ताओं ने हॉट मिक्स प्लांट स्थापित करने के लिए उपकरणों को उस संपत्ति में पहुँचाया, जहाँ से उन्होंने इसे संचालित करने का प्रस्ताव रखा था।

/

/

417

जोली जॉर्ज और ए. एन. आर. वी. जॉर्ज एलियास और एसोसिएशन और ओआरएस। [वी. रामसुब्रमणियन, जे.] ए.

/

(vi) कुछ राजनीतिक दलों के प्रति निष्ठा रखने वाले इलाके के कुछ सदस्यों द्वारा आपत्तियां उठाई गईं, जिसके कारण सुलह की बैठक हुई। हालाँकि, ग्राम पंचायत ने 12.05.2020 दिनांकित आदेश द्वारा आवेदन को अस्वीकार कर दिया। (vii) इसलिए, दिनांक 12.05.2020 के उक्त आदेश को चुनौती देते हुए रिट याचिकाकर्ताओं ने 2020 की WP (C) No.10381 वाली पहली रिट याचिका दायर की। रिट याचिकाओं को स्वीकार कर लिया गया और ग्राम पंचायत के आदेश के संचालन पर अंतरिम रोक भी लगा दी गई।

/

(viii) इसके बाद, कुछ रिट याचिकाएं दायर की गईं, जिनका विवरण यहां दर्ज करना आवश्यक नहीं हो सकता है। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि एक रिट याचिका में, उच्च न्यायालय ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति प्राप्त करने के बाद, संयंत्र स्थापित करने के लिए रिट याचिकाकर्ताओं को पुलिस सुरक्षा प्रदान की।

/

/

(ix) अंततः, रिट याचिकाकर्ताओं ने दूसरी रिट याचिका दायर कर यह घोषणा करने की मांग की कि केरल एमएसएमई अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त पावती प्रमाण पत्र के आधार पर, केरल पंचायत राज अधिनियम, 1994 के अंतर्गत लाइसेंस की आवश्यकता नहीं थी।

/

(x) विद्वान एकल न्यायाधीश ने वास्तव में केरल एमएसएमई अधिनियम के प्रबल प्रभाव से संबंधित प्रश्न में प्रवेश किए बिना कहा कि रिट याचिकाकर्ताओं का हॉट मिक्स प्लांट एक पोर्टेबल उपकरण था और यह 2019 के नियमों के अंतर्गत "भवन" शब्द की परिभाषा के भीतर नहीं आता है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह भी कहा कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा "स्थापना के लिए सहमति" के अनुदान के बाद, पंचायत की अनुमति केवल औपचारिक थी। डिवीजन बेंच ने भी इस विचार की पुष्टि की। यही कारण है कि पक्षकार इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए हैं।

/

8. विद्वान एकल न्यायाधीश और खंड पीठ के आदेश को नंगे पढ़ने से पता चलता है कि सबसे महत्वपूर्ण पहलू दृष्टिहीन हो गया है। मान लीजिए, रिट याचिकाकर्ताओं ने केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से इसे स्थापित करने के लिए सहमति प्राप्त की है। यह भी स्वीकार किया जाता है कि रिट याचिकाकर्ताओं ने इसके अंतर्गत एक पावती प्रमाण पत्र प्राप्त किया है

/

/

3 संक्षेप में, "1994 का अधिनियम"

418

/

[2023] 3 एस सी आर।

केरल एमएसएमई अधिनियम की धारा 5 (3)। केरल एमएसएमई अधिनियम की धारा 6 इस प्रकार है:

“6. स्वीकृति प्रमाणपत्र का प्रभाव।—(1) अ.

धारा 5 के अंतर्गत जारी पावती प्रमाण पत्र, सभी उद्देश्यों के लिए, इस तरह प्रभावी होगा जैसे कि यह धारा 2 के खंड (सी) में परिभाषित अनुमोदन है, इसके जारी होने की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए और उक्त तीन साल की अवधि की समाप्ति के बाद, ऐसे उद्यम को ऐसी समाप्ति की तारीख से छह महीने के भीतर धारा 2 के खंड (सी) में परिभाषित आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने होंगे:

/

बशर्ते कि पावती प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति को केरल धान भूमि और आर्द्रभूमि संरक्षण अधिनियम, 2008 (2008 का 28) में निहित प्रावधानों के विपरीत भूमि का उपयोग करने का अधिकार नहीं देगा और यह किसी व्यक्ति को केरल नगर और देश योजना अधिनियम, 2016 (2016 का 9) के अंतर्गत अधिसूचित मास्टर प्लान में निर्दिष्ट भूमि उपयोग के विचलन में भूमि का उपयोग करने का अधिकार भी नहीं देगा, जहां भी ऐसी योजना लागू है।

/

/

(2) उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट तीन वर्षों की अवधि के दौरान, कोई भी सक्षम प्राधिकारी धारा 2 के खंड (ग) में परिभाषित किसी भी अनुमोदन के उद्देश्य या उसके संबंध में कोई निरीक्षण नहीं करेगा। "

/

9. ऊपर निकाली गई धारा 6 (1) से यह देखा गया है कि एक पावती प्रमाण पत्र का प्रभाव होगा जैसे कि यह धारा 2 (सी) में परिभाषित एक अनुमोदन है। धारा 2 (सी) इस प्रकार है:-

"2.(ग) "अनुमोदन" का अर्थ है राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की स्थापना या संचालन के संबंध में किसी भी राज्य के विधि के अंतर्गत आवश्यक लाइसेंस, अनुमति, अनुमोदन, मंजूरी, पंजीकरण, सहमति, अनापत्ति प्रमाण पत्र और इसी तरह के अन्य दस्तावेज।

/

10. रिट याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आज जो निर्णय लिया गया है, वह 1994 के अधिनियम के अंतर्गत अनुमति की आवश्यकता है। लेकिन केरल एमएसएमई अधिनियम की धारा 10 न केवल अन्य कानूनों पर अधिनियम को ओवरराइडिंग प्रभाव प्रदान करती है, बल्कि 1994 के अधिनियम का एक विशिष्ट संदर्भ भी देती है। केरल एमएसएमई अधिनियम की धारा 10 इस प्रकार है:

/

"10. अन्य कानूनों पर इस अधिनियम का प्रबल प्रभाव।— (1) द.

ए के बावजूद, इस अधिनियम के प्रावधानों का प्रबल प्रभाव होगा।

/

तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उससे असंगत कुछ भी।

(2) विशेष रूप से और इस अधिनियम के पूर्वगामी प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे प्रावधान निम्नलिखित अधिनियमों में निहित कुछ भी असंगत होने के बावजूद प्रभावी होंगे और इन अधिनियमों के प्रावधानों को इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप संशोधित के रूप में पढ़ा जाएगा, अर्थात्:—

/

1. केरल पंचायत राज अधिनियम, 1994 (1994 का 13) 2. केरल नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का 20)

/

3. केरल दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1960 (1960 का 34)

4. केरल लिफ्ट एंड एस्केलेटर अधिनियम, 2013 (2013 का 18) 5. त्रावणकोर-कोचीन सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1955 (1955 का XVI)

/

6. मद्रास सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1939 (1939 का 3) "

11. इसलिए, रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा अपनी दूसरी रिट याचिका में की गई प्रार्थना, स्पष्ट रूप से वैधानिक प्रिस्क्रिप्शन के आलोक में दी जानी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से, विद्वान एकल न्यायाधीश और खंड पीठ दोनों ने इस सबसे महत्वपूर्ण पहलू की पूरी तरह से अनदेखी की।

/

12. हालाँकि, विरोध करने वालों की ओर से पेश विद्वान वकील श्री के. परमेश्वर ने तर्क दिया कि दो मुद्दे विचार के लिए उत्पन्न होते हैं, अर्थात् (i) क्या केरल एमएसएमई अधिनियम के अंतर्गत प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्राप्त स्व-प्रमाणन अपने आप में एक हॉट मिक्स प्लांट स्थापित करने के लिए पर्याप्त है; और (ii) क्या इस तरह के स्व-प्रमाणन के आलोक में, 1994 के अधिनियम और 2019 के नियमों के अंतर्गत पंचायत से किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

/

13. विरोध करने वालों के विद्वान वकील के अनुसार, केरल सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम सुविधा नियम, 2020 के नियम 3 में धारा 5 (3) के अंतर्गत पावती प्रमाण पत्र चाहने वाले सभी व्यक्तियों को फॉर्म-1 में विधिवत भरा हुआ स्व-प्रमाणन प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। इस प्रपत्र में केरल पंचायत भवन नियम, 2019 का पालन करने के लिए आवेदक का एक वचन है और इसलिए यह तर्क दिया जाता है कि रिट याचिकाकर्ता स्थानीय पंचायत से अनुमति की आवश्यकता से बच नहीं सकते हैं।

14. लेकिन उक्त तर्क को इस सरल कारण से कायम नहीं रखा जा सकता है कि अधिनियम के अंतर्गत विरचित गए नियम वैधानिक प्रावधानों के प्रभाव को रद्द नहीं कर सकते हैं। केरल एमएसएमई अधिनियम की धारा 10 (2) यह स्पष्ट करती है कि 1994 के अधिनियम के प्रावधानों को केरल एमएसएमई अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप संशोधित किया जाएगा। इसलिए, विरोध करने वाले अधिनियम के प्रावधानों के प्रभाव को रद्द करने के लिए नियमों से पीछे नहीं हट सकते हैं।

/

15. विद्वान वकील श्री के. परमेश्वर द्वारा यह तर्क दिया गया है कि हालाँकि उनके मुवक्किलों ने केरल एमएसएमई अधिनियम की धारा 10 की संवैधानिक वैधता को चुनौती नहीं दी है, लेकिन यह न्यायालय जनहित में प्रबलित और पूर्ण खंडों को पढ़ सकता है। विद्वान वकील के अनुसार, पंचायत का सार्वजनिक कर्तव्य है कि वह पर्यावरण प्रदूषण से अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर के क्षेत्रों और व्यक्तियों की रक्षा करे और एहतियाती सिद्धांत को लागू करने की आवश्यकता है। विद्वान वकील ने भरोसा किया

/

बृहन्मुंबई नगर निगम (एम. सी. जी. एम.) बनाम अभिलाष लाल और अन्य में इस न्यायालय के निर्णयों पर। 4 और ए. पी. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाम प्रो.एम. वी. नायडू (सेवानिवृत्त) और अन्य। 5.

/

16. लेकिन उपरोक्त तर्क पूरी तरह से गलत है। केरल एमएसएमई अधिनियम की धारा 10 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981, जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 जैसे किसी भी प्रदूषण नियंत्रण कानून के प्रावधानों को ओवरराइड नहीं करती है। केरल एमएसएमई अधिनियम 1994 के अधिनियम और कुछ अन्य स्थानीय अधिनियमों को दरकिनार करता है। यही कारण है कि रिट याचिकाकर्ताओं ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से "सहमति" ली है। एक बार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से

सहमति लेने के बाद, पर्यावरण की रक्षा के उद्देश्य से केरल एमएसएमई अधिनियम की धारा 10 को पढ़ने की आवश्यकता पैदा नहीं होती है।

/

/

17. यह तर्क कि पंचायत जमीनी स्तर की संस्था होने के नाते निर्णय लेने में भागीदारी का अधिकार रखती है, एक बार फिर गलत धारणा है। सभी पंचायतें मोटर योग्य सड़कें चाहती हैं। लेकिन अगर वे नहीं चाहते कि सड़क निर्माण सामग्री का निर्माण उनकी पंचायत के भीतर किया जाए, तो हमें नहीं पता कि इन सामग्रियों का आयात कहां से किया जा सकता है। इसलिए, इस न्यायालय के निर्णय पर आक्षेपकर्ताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा रखी गई निर्भरता

/

टी. एन. गोडावर्मन तिरुमुलपद बनाम में लाफार्ज उमियम माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड। भारत संघ और ओआरएस। **6**, भी गलत स्थान पर है।

4 (2020) 13 एससीसी 234 5 (1999) 2 एससीसी 718 6 (2011) 7 एससीसी 338 ए

/

421

जोली जॉर्ज और ए. एन. आर. वी. जॉर्ज एलियास और एसोसिएशन और ओआरएस। [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

18. वास्तव में, इस प्रश्न पर भी तर्क दिए गए थे कि क्या हॉट मिक्स प्लांट पोर्टेबल है या क्या यह एक अस्थायी या स्थायी संरचना आदि है। लेकिन हमें नहीं लगता कि उक्त प्रश्न में जाना आवश्यक है, क्योंकि केरल एमएसएमई अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त पावती प्रमाण पत्र ही रिट याचिकाकर्ता के पक्ष में मुद्दा उठाने के लिए पर्याप्त है।

/

19. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिकाकर्ता जो इनमें से तीन अपीलों में प्रतिवादी संख्या 1 है और इन अपीलों में से एक में अपीलार्थी दोनों रिट याचिकाओं में मांगी गई राहत का हकदार है। तदनुसार, रिट याचिकाकर्ता जॉर्ज एलियास एंड एसोसिएट्स द्वारा दायर अपील को अनुज्ञात जाती है, आक्षेपित आदेशों को दरकिनार कर दिया जाता है और जॉर्ज एलियास एंड एसोसिएट्स द्वारा दायर रिट याचिकाओं को अनुज्ञात जाती है। विरोध करने वालों, अर्थात् इलाके के लोगों द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया जाता है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

/

अंकित ज्ञान

अपीलों का निपटारा किया गया।

/

(सहायक: आरश चौधरी, एलसीआरए)

/

/

/

/